CBI enquiry into the alleged nexus between railway officials and corporate catering houses

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, for years together, at the instance of the Ministry of Railways, the entire catering system of Railways is being systematically dismantled at the initiative of a section of Railway officials to appease the big corporate houses, engaged in catering business. In 1990-91, sales turnover of departmental catering was Rs.203.98 crore over realisation of another Rs.213.51 crore as licence fees. As of December, 2012, the Railway transported over 25 million passengers daily, most of which are from economically weaker sections. These people are habitual of consuming Indian food items like *puri, roti-sabji/dal, rice-sabji/dal,* etc. But, the Railway Ministry is systematically making changes in the menu and introducing pizza, burgers, etc., at the instance of corporate houses. Earlier, the Railways used to supply uncooked *dal/sabji* to the commissioned vendors who, in turn, used to cook the same and sell to the passengers on payment. But, suddenly, vide order no. 23AC/Ctg/Menu & Rate/2013, dated 31st July, 2013, Senior Divisional Manager has revised the rate of 300 grams rice without *dal/sabji* to Rs.10/- and stopped supplying uncooked *dal/sabji* to commissioned vendors. So, the passengers are being compelled to bring cooked *dal/sabji* from their own kitchens and thus get frustrated on opting for pizza and burgers instead.

While demanding immediate withdrawal of the irrational order dated 31st July, 2013, and restoration of supply of previous menu to passengers on payment, I urge upon the Government to institute a high-level independent enquiry to unearth the nexus between a section of Railway officials down to the level of C.I.C. and corporate houses engaged in catering business in the Railways.

Unabated deaths of tribal children in Attappadi in Palakkad District of Kerala

डा.टी.एन. सीमा (केरल): माननीय उपसभापति जी, मैं इस वरिष्ठ सभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. lady Member is speaking. Let her speak.

डा.टी.एन. सीमा: यह केरल के आदिवासी अट्टापाडी इलाके में लगातार हो रही ...**(व्यवधान)**... आदिवासी शिशुओं की हत्या के बारे में है। सर, पिछले 20 महीनों में 60 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मृत्यु हुई है। अभी पिछले शनिवार में भी....**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप अच्छी हिन्दी बोलती हैं।

डा.टी.एन. सीमा: एक और आदिवासी शिशु की मौत हुई है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): माननीय उपसभापति जी, यह आपके लिए भी एक उदाहरण है। ...**(व्यवधान)**... आप भी अच्छी हिन्दी बोलते हैं, इसलिए आप भी हिन्दी बोला करें। ...**(व्यवधान)**...

डा.टी.एन. सीमा: सर, मेरा टाइम? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: सबके लिए है।

डा. टी.एन.सीमा: इसका मुख्य कारण कुपोषण है। ..(व्यवधान)..हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन की रिपोर्ट के अनुसार अट्टापाडी की आदिवासी गर्भवती महिलाओं में कुपोषण ज्यादा है। यह भी शिशु मौतों का एक कारण बन गया है। वहाँ से एक और शॉकिंग रिपोर्ट आ रही है कि अट्टापाडी में आदिवासी महिलाओं के अबॉर्शस और मिसकैरिज़ेज़ ज्यादा हो रहे हैं। एक साल में 77 अबॉर्शस हुए हैं और वहाँ की जनसंख्या सिर्फ़ 30 हजार है। माननीय प्रधान मंत्री जी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने भी वहाँ इंटरवीन किया है, लेकिन वहाँ की स्थिति में अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है।

सर, वहाँ पर अभी तक फॉरेस्ट राइट ऐक्ट इम्प्लिमेंट नहीं हुआ है। आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली गई है, लेकिन वापस नहीं की गई है। वहाँ के आदिवासियों को मनरेगा में भी पिछले कई महीनों से एक भी काम नहीं मिला है। वहाँ पर पूरी अव्यवस्था चल रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पंचायत के बीच में कोई कॉआर्डिनेशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपेक्षा करती हूं कि आप वहाँ पर तुंरत इंटरवीन कीजिए, नहीं तो अट्टापाडी के आदिवासियों की वंश हत्या होने की पूरी संभावना है। थैंक यू।

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

SHRI C.P. NARAYANAN (Kerala): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

†[**شری منوّر سلیم (اترپردیش)** : مہودے، میں اس سے اپنے آپ کو سمبدّ کرتا ہوں۔]

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री अनिल देसाई (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री रामकृष्णा रंगासायी (कर्णाटक): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Dr. Heptulla. ...*(Interruptions)*...

Slaughtering of milch animals

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, आपने आज मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अलाऊ किया है। ...**(व्यवधान)**...जीरो ऑवर में रेज़ तो करने दीजिए।

[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

SHRI C.M. RAMESH (Andhra Pradesh): There is a Zero Hour notice. ...*(Interruptions)*...

SHRI Y.S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): Sir, our issue has been. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Dr. Heptulla has been called. ...*(Interruptions)*... Please.

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला: सर, आप चेयर पर हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं बच्चों के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रही हूं। भारत से बड़ी तादाद में बीफ़ का एक्सपोर्ट होता है। यह ठीक है कि आज हम इक्नॉमिक सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, हमने बीफ़ के एक्सपोर्ट में भी तरक्की की है, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि ज्यादातर बीफ़, लगभग 70 फीसदी, यू.पी. से एक्सपोर्ट होता है। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, वह ठीक है, मगर इसके साथ-साथ इस होड़ से कि हम ज्यादा से ज्यादा बीफ़ एक्सपोर्ट करें, इसका निर्यात करें, इस होड़ की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ...**(व्यवधान)**...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल): बीफ़ एक्सपोर्ट नहीं होता है।

---

†Transliteration in Urdu Script.